1	2	3	4	5
22	इंदौर–उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक . . .	(–) 0.14	(+) 0.05	(–) 2.67
23	ग्वालियर–दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक . . .	(–) 0.27	(+) 2.73	(–) 4.99
24	विदिशा–भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक . .	( )	(+) 1.25	(+) 0.80
	कुल लाभ	(+)	(+) 9.24	(+) 25.20
	हानि	(–) 434.71	(–) 494.88	(–) 614.90

Export Commitments

3485. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in an attempt to prove that export commitments are adhered to, companies often opt to route exports that were being despatched by other companies through their companies and as a result thereof despite export obligations of enormous volume and value, little growth has been registered in our national capacity to export;

(b) whether Government are aware of this loophole in the export obligation rule;

(c) whether steps are being initiated to correct this anomaly; and

(d) if so, what is the estimated loss of potential incremental exports on account of such gaps in Policy implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) No' Sir. Export Obligations imposed by Foreign Collaborations, Letters of Intent, Industrial Licences and import of Capital Goods are to be fulfilled only by export of own manufacturers. Manufacturer exporteds who avail of the facility of advance licence also can export only their own manufactured products for fulfilment of export obligation. Only in the case of merchant exporters using Advance Licence Scheme it is possible to fulfil export obligation with products of specified supporting manufacturers. In such circumstances, there is no possibility of diversion of exports of other companies to fulfil export obligation receiving the exempt imported material.

(b) to (d) Do not arise.

शीतल पेय के उत्पादकों के लिए उत्पाद शुल्क में राहत

3486. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेयों का उत्पादन करने वाले लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों ने एक ज्ञापन दिया है, यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाह की है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में बेतहाशा वृद्धि किय जाने से शीतल पेय बनाने वाले लघु औद्योगिक एकक बन्द हो जाने के कगार पर है और उनकी वित्तीय

स्थिति को रुग्ण एककों की श्रेणी में धकेल रही है ; और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लघु औद्योगिक एककों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा): (क) और (ख) सरकार को वातित जल का निर्माण करने वाले यूनिटों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बड़े निर्माताओं या व्यापारियों के ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत वातित जल का निर्माण करने वाले लघु यूनिटों के लिए उत्पादन शुल्क में छूट, जो इनको 30 सितम्बर, 1987 तक उपलब्ध थी, पुन: बहाल करने के लिए अनुरोध किया गया था । उन्होंने वातित जल पर उत्पादन शुल्क के भार को [illegible] करने के लिए अनुरोध किया है ।

वातित जल पर उदाहरण मूल उत्पादन शुल्क में मार्च [illegible] कोई वृद्धि नहीं की गई है । वातित जल सहित विनिर्दिष्ट माल का निर्माण करने वाले लघु यूनिटों के लिए उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट को एक अक्तूबर, 1987 को संशोधित किया गया था ताकि ऐसे माल के मामले में, जो बड़े निर्माताओं या व्यापारी के ब्रांड नामों के अन्तर्गत लघु [illegible] द्वारा निर्मित किया जाता है [illegible] लाभ न दिये जा सकें । वातित जल का निर्माण [illegible] यूनिट लघु उद्य[illegible] हैं है । प्राप्त हुई रिपोर्टों से वातित जल का निर्माण करने वाले लघु यूनिटों की निकासियों के मूल्य में किसी कमी या इनके बड़ी संख्या में बन्द होने के कोई संकेत नहीं मिलते है ।

सरकार का वातित जल के लिए उत्पादन शुल्क की दरों में या वातित जल के लिए लागू लघु उद्योग छूट स्कीम में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Income-Tax collected from Cine Sector

3478. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the amount of income-tax collected from the cine sector during the last five years, year-wise; and

(b) what amount was spent for the welfare of the cine workers out of the amount so collected during the above period year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) Records of collections are not maintained industry-wise or trade-wise. Therefore it is not possible to obtain such information.

(b) the share of the Central Government from out of income-tax collections goes to the Consolidated Fund of India. Expenditure incurred cannot be correlated.

Sericulture Development in Andhra Pradesh

3488. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for the development of sericulture in Andhra Pradesh; and

(b) if so what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) and (b) In collaboration with various State Governments, including Andhra Pradesh, the Central Silk Board has formulated a National Sericulture Project for increasing production of mulbery raw silk in the country. The project envisages an additional production of 6765 tonnes by the end of the project period. The project has been proposed for World Bank Assistance and a Mission from the Bank is expected to visit India in September/October, 1988 to discuss details of the Project.

Small savings collections

3489. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that attractive terms of financial investments